

प्रेषक,

अनूप वधावन,  
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,  
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 10 दिसम्बर, 2009

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में पुरकाजी-लक्सर मार्ग पर लक्सर में लेबिल क्रांसिंग सं० 504 पर रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों ओर पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु तृतीय एवं अन्तिम किशत की धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 907/IV(2)/2008-47(कुम्भ)/2008 दिनांक 19.11.2008 एवं शासनादेश संख्या 895/IV(1)/2009-47(कुम्भ)/2008 दिनांक 27.7.2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 1770लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 1768.03 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, कुल रु. 1100लाख की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 3112/कु.मे./उपयोगिता दिनांक 26.11.2009, जिसके द्वारा उक्त रु. 1100लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया गया है, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु संस्तुति के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष रु. 668.03लाख (रु. छः करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का चार बराबर किशतों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के सापेक्ष 80प्रतिशत से अधिक उपयोग के बाद ही इस स्वीकृति के अधीन किसी धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
2. उक्त तृतीय किशत के विपरीत न्यूनतम निविदा (एल-1) के परिदृश्य में व्यय हेतु न्यूनतम धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जाएगा। आहरित से धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा।
3. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।



8. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
9. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 19.11.2008 के अनुसार लागू रहेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009-39(सा.)/2006-टी.सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रु. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 863/XXVII(2)/2009 दिनांक 18दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अनूप वधावन )  
सचिव।

संख्या : 177/ (1)/IV(1)/2009 तददिनांक। 18/12/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( सुभाष चन्द्र )  
अनुसचिव।